सुनील कुमार और अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य

19 जनवरी 2005

[अरिजीत पसायत और एस.एच. कपाड़िया, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860 :

धारा 302 सह धारा 149 - हत्या - विधिविरुद्ध जमाव - सामान्य उद्देश्य - आठ आरोपी एक जीप में एक साथ आए और मृतक को घेर लिया - जीप को शुरुआती चालू रखा गया - एक आरोपी ने मृतक के पेट पर चाकू से कई वार किए - अन्य सात, यानी अपीलकर्ताओं ने उस पर हॉकी स्टिक, लोहे की छड़ों और पाइपों के साथ हमला किया - हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे व्यक्तियों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई - घटना के बाद आरोपी उसी जीप में भाग गए - धारा 302 सह धारा 149 के तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया - औचित्य - अभिनिर्धारित किया गया, निचली अदालतों ने अपीलकर्ताओं के मामले में धारा 149 लागू करने और उन्हें दोषी ठहराने को उचित ठहराया - जब हथियारों से लैस कई व्यक्ति किसी पीड़ित पर हमला करते हैं, तो वे सभी वास्तविक हमले में भाग नहीं ले सकते हैं - इसलिए, प्रत्येक आरोपी द्वारा विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य स्थापित करना आवश्यक नहीं है।

धारा 149 - की प्रयोज्यता - रचनात्मक दायित्व अनिवार्य रूप से गैर - सामान्य उद्देश्य पर जोर और सामान्य आशय पर नहीं - सामान्य उद्देश्य, जब बनता है।

धारा 149 और धारा 34 - सामान्य उद्देश्य और सामान्य आशय - के बीच अंतर - चर्चा की गई।

आपराधिक मुकदमा - एफआईआर - मजिस्ट्रेट को एफआईआर भेजने में देरी - कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि ऐसे सभी मामलों में, अभियोजन पक्ष का संस्करण अविश्वसनीय हो जाता है - जहां तथ्यों पर, एफआईआर भेजने में कथित देरी के कारण के बारे में जांच अधिकारी से कोई सवाल नहीं किया गया था और जांच तुरंत शुरू की गई, अभिनिर्धारित किया गया , कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका।

शब्द और वाक्यांश - "उद्देश्य" - का अर्थ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक, सूचक का भतीजा, आठ आरोपियों से घिरा हुआ था। आरोपियों में से एक, अर्थात् 'आर' ने मृतक के पेट पर चाकू से कई वार किए, जबकि अन्य सात, यानी अपीलकर्ताओं ने उस पर हॉकी स्टिक, लोहे की छड़ और पाइप से हमला किया। इसके बाद आरोपी एक लाल जीप में भाग गए, जिसमें वे साथ आए थे। सत्र न्यायाधीश ने 'आर' को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और अन्य सात आरोपियों को धारा 302 के सह धारा 149 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया। हाई कोर्ट ने सजा बरकरार रखी. आर ने आगे कोई अपील नहीं की, जबकि बाकी आरोपियों ने वर्तमान अपील दायर की।

इस न्यायालय में अपील में, मुख्य प्रश्न भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की प्रयोज्यता से संबंधित उठाया गया, अपीलकर्ताओं ने दलील दी कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उनके द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य का पीछा किया गया था; भले ही यह मान लिया जाए जैसा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया है कि वे एक ही जीप में आए थे और विभिन्न हथियारों से लैस थे, जो यह स्थापित नहीं करता है कि उनका एक ही उद्देश्य था, और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि ऐसा सामान्य वस्तु 'आर' जिसने कथित तौर पर घातक चाकू से वार किया, उसने कथित गैरकानूनी सभा के उद्देश्य को पूरा किया; और यह कि उच्च न्यायालय ने उसके समक्ष उठाई गई विभिन्न याचिकाओं पर उचित ढंग से विचार नहीं किया

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1. निचली अदालतों द्वारा अपीलकर्ताओं के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 149 लागू करना उचित था। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के सह धारा 149 के तहत सही दोषी ठहराया गया है।

1.2. भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की नींव रचनात्मक दायित्व पर है जो इसके संचालन के लिए अनिवार्य शर्त है। जो सामान्य उद्देश्य पर है न कि सामान्य आशय पर। किसी गैरकानूनी जमावड़े में मात्र उपस्थिति किसी व्यक्ति को तब तक उत्तरदायी नहीं बना सकती जब तक कि वहां कोई सामान्य उद्देश्य न हो और वह उस सामान्य उद्देश्य से प्रेरित हो और वह उद्देश्य धारा 141 में निर्धारित उद्देश्यों में से एक हो।

1.3. उद्देश्य शब्द का अर्थ उद्देश्य या प्रारूप है और, इसे 'सामान्य' बनाने के लिए, इसे सभी द्वारा साझा किया जाना चाहिए। आपसी परामर्श के बाद स्पष्ट सहमति से एक सामान्य उद्देश्य बनाया जा सकता है, लेकिन यह किसी भी तरह से आवश्यक नहीं है। इसका गठन किसी भी स्तर पर विधानसभा के सभी या कुछ सदस्यों द्वारा किया जा सकता है और अन्य सदस्य

इसमें शामिल हो सकते हैं और इसे अपना सकते हैं। एक बार बनने के बाद, इसे उसी तरह जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। इसे किसी भी स्तर पर संशोधित या बदला जा सकता है या छोड़ा जा सकता है। धारा 149 में प्रकट होने वाली अभिव्यक्ति 'सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में' को सख्ती से 'सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए' के बराबर माना जाना चाहिए। उद्देश्य की प्रकृति के आधार पर इसे तुरंत सामान्य उद्देश्य से जोड़ा जाना चाहिए, उद्देश्य का समुदाय होना चाहिए और उद्देश्य केवल एक विशेष चरण तक ही मौजूद रह सकती है, उसके बाद नहीं। किसी गैरकानूनी जमावड़े के सदस्यों के पास कुछ बिंदु तक वस्तु का समुदाय हो सकता है जिसके बाद वे अपने उद्देश्यों में भिन्न हो सकते हैं और प्रत्येक सदस्य के पास उनके सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने वाले ज्ञान के अनुसार न केवल भिन्नता हो सकती है। उसके आदेश पर जानकारी, लेकिन यह भी कि वह उद्देश्य के समुदाय को किस हद तक साझा करता है, और इसके परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 149 का प्रभाव एक ही सभा के विभिन्न सदस्यों पर अलग-अलग हो सकता है।

1.4. 'सामान्य उद्देश्य ' 'सामान्य आशय ' से भिन्न है क्योंकि इसमें हमले से पहले किसी पूर्व संगीत कार्यक्रम और मन की आम बैठक की आवश्यकता नहीं होती है। यह पर्याप्त है यदि प्रत्येक का उद्देश्य एक ही है और उनकी संख्या पांच या अधिक है और वे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सभा के रूप में कार्य करते हैं, घटना के एक विशेष चरण में विधिविरुद्ध सभा का सामान्य उद्देश्य क्या है, यह अनिवार्य रूप से एक प्रश्न है। तथ्य को सभा की प्रकृति, सदस्यों द्वारा ले जाने वाले हथियारों और घटना स्थल पर या उसके निकट सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए।

1.5. धारा 149 के दूसरे अंग में प्रयुक्त शब्द 'जानता था' का तात्पर्य संभावना से अधिक कुछ है और इसे 'जानना होगा' का अर्थ नहीं दिया जा सकता। सकारात्मक ज्ञान आवश्यक है. जब कोई अपराध सामान्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो यह आम तौर पर एक अपराध होगा जिसके बारे में गैरकानूनी सभा के सदस्यों को पता था कि सामान्य उद्देश्य के लिए मुकदमा चलाने की संभावना है।

*चिक्कारांगे गौड़ा और अन्य बनाम मैसूर राज्य,***एआईआर (1956) एससी 731 और***चंद्रा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य* **(2004) 5 एससीसी 141, संदर्भित।**

2. प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य से यह स्थापित हो गया है कि सभी आठ आरोपी हथियारों से लैस थे, उन्होंने मृतक को घेर लिया और वास्तव में दूसरों को उसे बचाने के लिए मृतक के पास

जाने से रोका। वे एक ही जीप में एक साथ आए थे और घटना के बाद जीप से चले गए। जीप को शुरुआती स्थिति में रखा गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिरह में बचाव पक्ष ने इस तथ्य को उजागर किया कि आरोपी व्यक्तियों ने मृतक को घेर लिया और जो लोग मृतक को बचाने के लिए जाना चाहते थे उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर रोका। परीक्षण न्यायालय और हाई कोर्ट ने तथ्यात्मक स्थिति का विस्तार से विश्लेषण किया है और उपरोक्त प्रासंगिक कारकों को इंगित किया है। इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की प्रयोज्यता के बारे में नीचे दी गई अदालतों के निष्कर्ष में कोई खामी नहीं है।

3. इसे सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जब भी ए को संबंधित मजिस्ट्रेट को एफआईआर भेजने में कुछ देरी होती है, तो अभियोजन संस्करण अविश्वसनीय हो जाता है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है, तत्काल मामले में जांच तुरंत शुरू की गई और जांच में कुछ कदम उठाए गए। इसलिए, इस दलील में कोई दम नहीं है कि प्रासंगिक समय पर कोई एफआईआर मौजूद नहीं थी। इसके अतिरिक्त, एफआईआर को कथित तौर पर देरी से भेजने के कारण के बारे में जांच अधिकारी से कोई सवाल नहीं पूछा गया। यदि ऐसा किया गया होता तो जांच अधिकारी परिस्थितियों को स्पष्ट कर सकते थे। ऐसा नहीं किये जाने पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

4. जहां तक गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी का सवाल है, फिर से जांच अधिकारी से विशेष रूप से कोई सवाल नहीं पूछा गया कि बयान दर्ज करने में देरी क्यों हुई। इसके उलट गवाहों ने खुद ही इस बात का संकेत दिया है कि देरी क्यों हुई. अत: इस संबंध में अपीलकर्ताओं की दलील में कोई दम नहीं है।

5. जिन गवाहों के चश्मदीद गवाह होने का दावा किया गया था, उनमें से पीडब्लू-3 और पीडब्लू-5 रिश्तेदार नहीं थे और किसी भी स्थिति में, किसी अन्य जगह के थे। भले ही पीडब्लू 1, 2 और 4 मृतक से संबंधित थे, पीडब्लू-1 एक ट्रैफिक कांस्टेबल था और जैसा कि रिकॉर्ड पर सबूत स्पष्ट रूप से स्थापित करता है, वह ट्रैफिक कांस्टेबल के रूप में घटनास्थल के पास एक स्थान पर तैनात था। इसलिए उनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता. अन्य गवाहों ने भी बताया है कि वे घटना स्थल पर कैसे पहुंचे। ऐसा होने पर, यह दलील कि स्वतंत्र गवाहों की जांच नहीं की गई है, बिना किसी तथ्य के है। दो स्वतंत्र गवाहों की जांच की गई है जिन्होंने रिश्तेदारों के साक्ष्य की पुष्टि की है।

6. यह आलोचना कि मृतक को बचाने के लिए रिश्तेदार आगे नहीं आए, इस आशय के सबूतों को ध्यान में रखते हुए भी कोई तथ्य नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों ने उन लोगों को धमकी दी थी जो हस्तक्षेप करना चाहते थे और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

7. जहां हमलावरों का एक समूह, जो गैरकानूनी सभा के सदस्य थे, उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में अपराध करने के लिए आगे बढ़ते हैं, गवाहों के लिए अक्सर उनमें से प्रत्येक द्वारा निभाई गई वास्तविक भूमिका का वर्णन करना संभव नहीं होता है और कब हथियारों से लैस कई व्यक्ति इच्छित पीड़ित पर हमला करते हैं, वे सभी वास्तविक हमले में भाग नहीं ले सकते हैं। इसलिए, अभियोजन पक्ष के लिए यह स्थापित करना आवश्यक नहीं था कि प्रत्येक अभियुक्त द्वारा किया गया विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य क्या था।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2005 की आपराधिक अपील संख्या 123।

डीबी क्रिमिनल अपील संख्या 646 ऑफ़ 2000 में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 10/11/2003 से।

साथ

2005 की आपराधिक अपील संख्या 124, 125, 126, 127, और 128।

आपराधिक अपील संख्या 123/2005 में अपीलकर्ता के लिए के वी मोहन, योगेश कुमार दुल्लर, अजय भल्ला, अनूप खुल्लर, ए के यादव और आर रमेश कुमार।

आपराधिक अपील संख्या 124/2005 में अपीलकर्ता के लिए डीएस चौधरी, एलएस चौधरी और वीएन रघुपति।

आपराधिक अपील संख्या 125/2005 में अपीलकर्ता के लिए एस आर बाजवा, सुशील कुमार जैन, एच डी थानवी, ए पी धमीजा, राम निवास, पुनीत जैन और सुश्री प्रतिभा जैन।

आपराधिक अपील संख्या 126-128/2005 में अपीलकर्ता के लिए मुल्ख राज विज, (ए.सी.)।

प्रत्यर्थी /कैविएटर मनीष कुमार की ओर से जगदीप धनखड़, अनिल कर्णवाल, डॉ. केपीएस दलाल और डॉ. सुशील बलवाड़ा और राजस्थान राज्य के लिए अंसार अहमद चौधरी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति गण

अनुमति प्रदान की गयी।

ये सभी अपीलें राजस्थान उच्च न्यायालय के सामान्य फैसले के खिलाफ निर्देशित हैं, जिसके द्वारा वर्तमान अपीलकर्ताओं सहित आठ आरोपी व्यक्तियों द्वारा की गई अपीलों का निपटारा कर दिया गया था। जबकि हरीश चंद्र के बेटे रमेश को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास और डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ 1,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी। अन्य सात यानी वर्तमान अपीलकर्ताओं 4 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के सह धारा 149 भारतीय दंड संहिता के साथ दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक को डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ 1,000 रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ा। आठ आरोपियों में से प्रत्येक को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के तहत दोषी ठहराया गया और दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। हरीश चंद्र के बेटे रमेश, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था, ने कोई अपील नहीं की है, जबकि बाकी सात आरोपियों ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

मुकदमे के दौरान सामने आया अभियोजन पक्ष का विवरण इस प्रकार है:

29 अक्टूबर 1998 को लगभग 11 बजे मुखबिर योगेन्द्र सिंह (पीडब्लू-1) ने रोडवेज बस स्टैंड झुंझुनू के पुलिस अधिकारी फूलचंद को लिखित रिपोर्ट सौंपी। अन्य बातों के साथ-साथ रिपोर्ट में कहा गया कि उक्त दिन सुबह लगभग 10 बजे मुखबिर बस स्टैंड के पास ट्रैफिक पॉइंट पर खड़ा था। वहां दो अन्य गवाह यानी सुरेंद्र और अजय भी थे. अचानक उन्हें पास की एक चाय की दुकान के सामने से शोर की आवाज़ सुनाई दी। तीनों उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि सूचना देने वाले का भतीजा, सुमेर सिंह (बाद में 'मृतक' के रूप में संदर्भित) अपीलकर्ताओं से घिरा हुआ था, जो हॉकी, लोहे की छड़ और पाइप आदि से लैस थे, जबकि रमेश कुमार एक चाकू था. रमेश कुमार ने मृतक के पेट पर चाकू से कई वार किए और अन्य लोगों ने हॉकी, लोहे की रॉड और पाइप से उसे घायल कर दिया। मृतक को घायल करने के बाद हमलावर एक लाल जीप संख्या आरजे-19/सी-6255 में सवार होकर घटनास्थल से भाग गए, जिसमें वे एक साथ आए थे। इस घटना को अन्य गवाहों चन्द्र शेखर और कृष्ण कुमार ने देखा था। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि मृतक को पूर्व दुश्मनी के चलते प्रताड़ित किया गया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस स्टेशन झुंझुनू में धारा 302, 147, 148 और 149 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराधों के लिए औपचारिक एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू हुई। घटना का साइट

प्लान तैयार किया गया। मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के खून से सने कपड़े जब्त कर लिए गए हैं। घटना स्थल से कंट्रोल मिट्टी व खून से सनी मिट्टी उठायी गयी. आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया और उनकी निशानदेही पर कुछ हथियार और जीप भी बरामद कर ली गई। जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया. मुकदमा विद्वान सत्र न्यायाधीश, झुंझुनू द्वारा संचालित किया गया। अपीलकर्ताओं और रमेश के खिलाफ वैकल्पिक 302/149 भारतीय दंड संहिता में धारा 147, 148,302 के तहत आरोप तय किए गए, जिन्होंने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का दावा किया। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 21 गवाहों से पूछताछ की और 61 दस्तावेज़ प्रदर्शित किये। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 313 के तहत अपने स्पष्टीकरण में, आरोपी व्यक्तियों ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि गवाह पक्षपातपूर्ण थे और झूठ बोल रहे थे क्योंकि वे उनके करीबी रिश्तेदार थे। मृतक और गुटबाजी के कारण सरासर झूठा आरोप लगाया गया था। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद सत्र न्यायाधीश ने ऊपर बताए अनुसार अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। सभी आठ आरोपियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जिसने जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलों को खारिज कर दिया और दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा।

वर्तमान अपीलों के समर्थन में विभिन्न अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा सामान्य बिंदुओं का आग्रह किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की प्रयोज्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने उठाई गई विभिन्न दलीलों पर ठीक से विचार नहीं किया, यानी (1) इलाका मजिस्ट्रेट को एफआईआर की प्रति भेजने में अस्पष्ट देरी; (2) स्वतंत्र गवाहों की जांच न करना; (3) चश्मदीद गवाह होने का दावा करने वाले गवाहों के साक्ष्य में विसंगतियां, जो वास्तव में मृतक से संबंधित थे; और (4) अभियोजन पक्ष के गवाह, विशेष रूप से रिश्तेदार, कि वे किसी विशेष समय पर घटना स्थल पर कैसे थे।

यह बताया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 को लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी तत्व मौजूद नहीं थे। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि अपीलकर्ताओं द्वारा कोई सामान्य वस्तु का पीछा किया गया था। भले ही इसे स्वीकार कर लिया जाए, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया है कि वे एक ही जीप में आए थे और विभिन्न हथियारों से लैस थे, जो यह स्थापित नहीं करता है कि उनके पास एक ही वस्तु थी। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि ऐसे सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में रमेश, जिसके बारे में कहा जाता है कि

उसने घातक चाकू से वार किया था, ने कथित गैर विधिविरुद्ध जमाव के उद्देश्य को पूरा किया। जिन पाँच गवाहों के चश्मदीद गवाह होने का दावा किया गया था उनमें से तीन करीबी रिश्तेदार थे। उनके बयान भी जांच के तुरंत बाद दर्ज नहीं किए गए और वास्तव में कुछ मामलों में दो दिन बाद और एक मामले में लगभग दो सप्ताह बाद दर्ज किए गए। तथ्य यह है कि एफआईआर दर्ज होने के काफी समय बाद मजिस्ट्रेट को भेजी गई एफआईआर स्वयं यह स्थापित करती है कि पुलिस अधिकारियों और मृतक के रिश्तेदारों, जिनमें मुखबिर और तथाकथित चश्मदीद गवाह और आरोपी व्यक्ति शामिल थे, की ओर से विचार-विमर्श किया गया था। झूठा फंसाया गया है. वर्तमान अपीलकर्ताओं के पास मृतक के प्रति कोई शत्रुता रखने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था। यदि चश्मदीद गवाह होने का दावा करने वाले लोग वास्तव में घटनास्थल पर मौजूद थे, तो उनका सामान्य और स्वाभाविक आचरण मृतक को बचाना होता जो कि नहीं किया गया है। हालांकि अभियोजन पक्ष का कथन यह है कि अपीलकर्ताओं ने मृतक पर अंधाधुंध हमला किया, केवल तीन खरोंचें पाई गईं। जैसा कि परीक्षण न्यायालय के निष्कर्षों से स्पष्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 का दूसरा भाग, जो कथित अपराध किए जाने की संभावना के ज्ञान से संबंधित है, उस संबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था। साक्ष्य से कोई भी सामान्य उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। उद्देश्य अधिक से अधिक हो सकता है, भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि वही अस्तित्व में था, मृतक को दंडित करना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना या कुछ चोट पहुंचाना। अभियोजन पक्ष द्वारा इन संभावनाओं से इंकार नहीं किया गया है। यह नहीं दर्शाया गया है कि वास्तविक उद्देश्य मृतक की हत्या थी। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वर्तमान अपीलकर्ताओं को पता था कि हत्या होने की संभावना है। परीक्षण न्यायालय और हाई कोर्ट का निष्कर्ष कि वर्तमान अपीलकर्ताओं ने मृतक को बचाने के लिए दूसरों की हत्या या गर्भपात के प्रयासों को बढ़ावा दिया, किसी भी ठोस सबूत द्वारा समर्थित नहीं है। घटना की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है और इसका कोई सटीक कारण स्थापित नहीं है कि आरोपी अपीलकर्ता एक सामान्य उद्देश्य का पीछा करके मृतक के जीवन को क्यों ख़त्म कर देंगे। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि कोई पूर्वकल्पित वस्तु भी थी, तो उस पर अधिकतम धारा 304 भारतीय दंड संहिता लग सकती है, न कि धारा 302 आईपीसी।

जवाब में, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू के बयान। अपीलकर्ताओं द्वारा निभाई गई भूमिका को स्पष्ट रूप से स्थापित करें। घटना से पहले, घटना के दौरान और घटना के बाद उनका आचरण स्पष्ट रूप से उस सामान्य उद्देश्य को स्थापित करता है जिसका वे पीछा कर रहे थे। आईओ से कोई विशेष सवाल नहीं पूछा गया कि देरी क्यों हुई, जैसा कि

अपीलकर्ताओं ने दावा किया है और इसके विपरीत गवाहों ने स्वयं कारणों का संकेत दिया है कि वे घटना स्थल पर क्यों थे और कुछ समय बाद उनके बयान क्यों दर्ज किए गए थे। इसी तरह का प्रभाव सूचक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की दलील का भी है।

मुख्य प्रश्न भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की प्रयोज्यता है। कहा गया प्रावधान रचनात्मक दायित्व पर आधारित है जो इसके संचालन के लिए अनिवार्य शर्त है। जोर सामान्य उद्देश्य पर है न कि सामान्य आशय पर। किसी गैरकानूनी जमावड़े में मात्र उपस्थिति किसी व्यक्ति को तब तक उत्तरदायी नहीं बना सकती जब तक कि वहां कोई सामान्य उद्देश्य न हो और वह उस आम उद्देश्य से प्रेरित हो और वह उद्देश्य धारा 141 में निर्धारित उद्देश्यों में से एक हो। जहां एक गैरकानूनी जमावड़े का सामान्य उद्देश्य साबित नहीं होता है, आरोपी व्यक्तियों को धारा 149 की मदद से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सभा में पांच या अधिक व्यक्ति शामिल थे और क्या उक्त व्यक्तियों ने एक या अधिक सामान्य उद्देश्यों का मनोरंजन किया था, जैसा कि धारा 141 में निर्दिष्ट है। ऐसा नहीं किया जा सकता है कानून के एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निर्धारित किया गया है कि जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कृत्य साबित नहीं होता है, जिस पर गैरकानूनी सभा का सदस्य होने का आरोप लगाया जाता है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि वह ऐसी सभा का सदस्य है। केवल एक चीज की आवश्यकता है कि उसे यह समझना चाहिए कि सभा गैरकानूनी थी और धारा 141 के दायरे में आने वाले किसी भी कार्य को करने की संभावना थी। 'उद्देश्य ' शब्द का अर्थ है उद्देश्य या प्रारूप और, इसे बनाने के लिए 'सामान्य', इसे सभी को साझा करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उद्देश्य उन व्यक्तियों के लिए सामान्य होना चाहिए, जो सभा की रचना करते हैं, अर्थात, उन सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए और इससे सहमत होना चाहिए। आपसी परामर्श के बाद स्पष्ट सहमति से एक सामान्य उद्देश्य बनाया जा सकता है, लेकिन यह किसी भी तरह से आवश्यक नहीं है। इसका गठन किसी भी स्तर पर विधानसभा के सभी या कुछ सदस्यों द्वारा किया जा सकता है और अन्य सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं और इसे अपना सकते हैं। एक बार बन जाने के बाद, इसे वैसा ही बने रहने की आवश्यकता नहीं है। इसे किसी भी स्तर पर संशोधित या बदला जा सकता है या छोड़ा जा सकता है। धारा 149 में प्रकट होने वाली अभिव्यक्ति 'सामान्य वस्तु के अभियोजन में' को सख्ती से 'सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए' के बराबर माना जाना चाहिए। वस्तु की प्रकृति के आधार पर इसे तुरंत सामान्य उद्देश्य से जोड़ा जाना चाहिए। उद्देश्य का समुदाय अवश्य होना चाहिए और उद्देश्य केवल एक विशेष अवस्था तक ही अस्तित्व में रह सकती है, उसके बाद नहीं। किसी गैरकानूनी

जमावड़े के सदस्यों के पास कुछ बिंदु तक उद्देश्य का समुदाय हो सकता है जिसके बाद वे अपने उद्देश्यों में भिन्न हो सकते हैं और प्रत्येक सदस्य के पास उनके सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने वाले ज्ञान के अनुसार न केवल भिन्नता हो सकती है। उसके आदेश पर जानकारी, लेकिन यह भी कि वह उद्देश्य के समुदाय को किस हद तक साझा करता है, और इसके परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 149 का प्रभाव एक ही सभा के विभिन्न सदस्यों पर अलग-अलग हो सकता है।

'सामान्य उद्देश्य ' 'सामान्य आशय ' से भिन्न है क्योंकि इसमें हमले से पहले किसी पूर्व संगीत कार्यक्रम और मन की आम बैठक की आवश्यकता नहीं होती है। यह पर्याप्त है यदि प्रत्येक की दृष्टि में एक ही उद्देश्य हो और उनकी संख्या पाँच या अधिक हो और वे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सभा के रूप में कार्य करें। किसी सभा का 'सामान्य उद्देश्य' उसे बनाने वाले सदस्यों के कृत्यों और भाषा से तथा आस-पास की सभी परिस्थितियों पर विचार करके सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसे विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपनाए गए आचरण के तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। घटना के किसी विशेष चरण में गैरकानूनी जमावड़े का सामान्य उद्देश्य क्या है, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है जिसे जमाव की प्रकृति, सदस्यों द्वारा उठाए गए हथियारों और सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। घटना स्थल के पास. कानून के तहत यह आवश्यक नहीं है कि किसी गैरकानूनी सामान्य उद्देश्य के साथ गैरकानूनी जमावड़े के सभी मामलों में उसे कार्रवाई में तब्दील किया जाए या सफल किया जाए। धारा 141 के स्पष्टीकरण के तहत, एक सभा जो एकत्रित होने पर गैरकानूनी नहीं थी, बाद में गैरकानूनी हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी सभा को ग़ैरक़ानूनी बनाने के लिए जो आशय या उद्देश्य आवश्यक है वह प्रारंभ में ही अस्तित्व में आ जाए। गैरकानूनी इरादा बनाने का समय महत्वपूर्ण नहीं है। कोई सभा, जो प्रारंभ में या उसके कुछ समय के लिए भी वैध है, बाद में गैरकानूनी हो सकती है। दूसरे शब्दों में, यह घटना के दौरान घटनास्थल पर विकसित हो सकता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में दो भाग होते हैं। धारा के पहले भाग का अर्थ है कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला अपराध ऐसा होना चाहिए जो सामान्य उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से किया गया हो। अपराध को पहले भाग के अंतर्गत आने के लिए, अपराध को गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य से तुरंत जोड़ा जाना चाहिए, जिसका आरोपी सदस्य था। भले ही किया गया अपराध सभा के सामान्य उद्देश्य के सीधे अभियोजन में न हो, फिर भी यह धारा 141 के अंतर्गत आ सकता है, यदि यह माना जा सकता है कि अपराध ऐसा

था जैसा सदस्यों को पता था कि ऐसा होने की संभावना है और यही है अनुभाग के दूसरे भाग में आवश्यक है। सभा के सदस्य जिस उद्देश्य के लिए प्रस्थान करते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं वह उद्देश्य है। यदि सभी सदस्यों द्वारा वांछित उद्देश्य एक ही है, तो जिस उद्देश्य का अनुसरण किया जा रहा है उसका ज्ञान सभी सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है और वे इस बात पर आम सहमति रखते हैं कि इसे उचित रूप से एकत्र किया जा सकता है सभा की प्रकृति से , किसी वस्तु को मानव मन में ग्रहण किया जाता है, और यह केवल एक मानसिक दृष्टिकोण है, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सकता है और, आशय की तरह, आम तौर पर उस कार्य से इकट्ठा किया जाना चाहिए जो व्यक्ति करता है और उसके परिणाम। हालाँकि उन परिस्थितियों में कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता है, जिनमें से सामान्य उद्देश्य को बाहर निकाला जा सकता है, इसे उचित रूप से सभा की प्रकृति, उसके पास मौजूद हथियारों और घटना के समय या उससे पहले या बाद के व्यवहार से एकत्र किया जा सकता है। अनुभाग के दूसरे भाग में प्रयुक्त शब्द 'जानता था' का अर्थ संभावना से अधिक कुछ है और इसे 'जानना होगा' का अर्थ नहीं दिया जा सकता। सकारात्मक ज्ञान आवश्यक है. जब कोई अपराध सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किया जाता है, तो यह आम तौर पर एक अपराध होगा जिसके बारे में गैरकानूनी सभा के सदस्यों को पता था कि सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना है। हालाँकि, यह विपरीत प्रस्ताव को सत्य नहीं बनाता है; ऐसे मामले हो सकते हैं जो दूसरे भाग में आएंगे लेकिन पहले भाग में नहीं। धारा 149 के दोनों भागों के बीच के अंतर को नज़रअंदाज़ या ख़त्म नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक मामले में यह निर्धारित करने का मुद्दा होगा कि क्या किया गया अपराध पहले भाग के अंतर्गत आता है या यह एक अपराध था जैसे कि विधानसभा के सदस्यों को पता था कि सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में प्रतिबद्ध होने की संभावना है और यह अपराध के अंतर्गत आता है। दूसरा हिस्सा। हालाँकि, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जो पहले भाग के भीतर होंगे लेकिन सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध आम तौर पर, यदि हमेशा नहीं, तो दूसरे भाग के भीतर होंगे, अर्थात्, ऐसे अपराध जिनके बारे में पार्टियों को पता था कि उनके प्रतिबद्ध होने की संभावना है सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में. (देखना *चिक्कारांगे गौड़ा और अन्य बनाम मैसूर राज्य*, एआईआर (1956) एससी 731)।

इन पहलुओं पर हाल ही में प्रकाश डाला गया चंद्रा *और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य*, [2004] 5 एससीसी 141।

ऊपर देखे गए तथ्यात्मक परिदृश्य में, परीक्षण न्यायालय और हाई कोर्ट ने यह मानने के लिए कई प्रासंगिक पहलुओं का उल्लेख किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 लागू है।

प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य से यह स्थापित हुआ है कि सभी आठ आरोपी हथियारों से लैस थे, उन्होंने मृतक को घेर लिया और वास्तव में अन्य लोगों को मृतक के पास उसे बचाने के लिए जाने से रोका। वे एक ही जीप में एक साथ आए थे और घटना के बाद जीप से चले गए। एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक कारक, जिस पर परीक्षण न्यायालय और हाई कोर्ट ने गौर किया है, वह यह है कि जीप को शुरुआती स्थिति में रखा गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिरह में बचाव पक्ष ने इस तथ्य को उजागर किया कि आरोपी व्यक्तियों ने मृतक को घेर लिया और जो लोग मृतक को बचाने के लिए जाना चाहते थे उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर रोका। परीक्षण न्यायालय और हाई कोर्ट ने तथ्यात्मक स्थिति का विस्तार से विश्लेषण किया है और उपरोक्त प्रासंगिक कारकों को इंगित किया है। इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की प्रयोज्यता के बारे में नीचे दी गई अदालतों के निष्कर्ष में कोई खामी नहीं है।

इलाका मजिस्ट्रेट को एफआईआर भेजने में कथित देरी पर बहुत जोर दिया गया। एफआईआर 29/10/1999 को लगभग 11 बजे दर्ज की गई और 30/10/1999 को लगभग 12 बजे मजिस्ट्रेट तक पहुंची। इसे सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जब भी संबंधित मजिस्ट्रेट को एफआईआर भेजने में कुछ देरी होती है, तो अभियोजन पक्ष का संस्करण अविश्वसनीय हो जाता है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है, तत्काल मामले में जांच तुरंत शुरू की गई और जांच में कुछ कदम उठाए गए। इसलिए, इस दलील में कोई दम नहीं है कि प्रासंगिक समय पर कोई एफआईआर मौजूद नहीं थी। इसके अतिरिक्त, एफआईआर को कथित तौर पर देरी से भेजने के कारण के बारे में जांच अधिकारी से कोई सवाल नहीं पूछा गया। यदि ऐसा किया गया होता तो जांच अधिकारी परिस्थितियों को स्पष्ट कर सकते थे। ऐसा नहीं किये जाने पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

जहां तक गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी का सवाल है, यहां भी जांच अधिकारी से विशेष रूप से कोई सवाल नहीं पूछा गया कि बयान दर्ज करने में देरी क्यों हुई। इसके उलट गवाहों ने खुद ही इस बात का संकेत दिया है कि देरी क्यों हुई. अत: इस संबंध में अपीलकर्ताओं की दलील में कोई दम नहीं है।

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह भी बताया है कि हालांकि जिस स्थान पर कथित घटना हुई थी, वह एक व्यस्त इलाके में था, किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी। यह भी कहा गया कि रिश्तेदारों ने यह नहीं बताया कि वे घटनास्थल पर कैसे पहुंचे। यहां भी तथ्यात्मक स्थिति कुछ और ही है। जिन गवाहों के चश्मदीद गवाह होने का दावा किया गया था,

उनमें से चंद्र शेखर (पीडब्लू-3) और नरेंद्र सिंह (पीडब्लू-5) रिश्तेदार नहीं थे और किसी भी स्थिति में कहीं और के थे। भले ही पीडब्लू. 1, 2 और 4 मृतक से संबंधित थे, पीडब्लू-1 एक ट्रैफिक कांस्टेबल था और जैसा कि रिकॉर्ड पर सबूत स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि वह ट्रैफिक कांस्टेबल के रूप में घटनास्थल के पास एक स्थान पर तैनात था। इसलिए उनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता. अन्य गवाहों ने भी बताया है कि वे घटना स्थल पर कैसे पहुंचे। ऐसा होने पर, यह दलील कि स्वतंत्र गवाहों की जांच नहीं की गई है, बिना किसी तथ्य के है। दो स्वतंत्र गवाहों की जांच की गई है जिन्होंने रिश्तेदारों के साक्ष्य की पुष्टि की है।

यह आलोचना कि मृतक को बचाने के लिए रिश्तेदार आगे नहीं आए, भी बिना किसी तथ्य के है, जैसा कि ऊपर उल्लेखित सबूतों के मद्देनजर है कि आरोपी व्यक्तियों ने उन लोगों को धमकी दी थी जो हस्तक्षेप करना चाहते थे और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

जहां हमलावरों का एक समूह, जो गैरकानूनी जमाव के सदस्य थे, उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में अपराध करने के लिए आगे बढ़ते हैं, गवाहों के लिए उनमें से प्रत्येक द्वारा निभाई गई वास्तविक भूमिका का वर्णन करना अक्सर संभव नहीं होता है और जब कई व्यक्ति हथियारबंद होते हैं इच्छित पीड़ित पर हथियारों से हमला करने पर, वे सभी वास्तविक हमले में भाग नहीं ले सकते हैं। इसलिए, अभियोजन पक्ष के लिए यह स्थापित करना आवश्यक नहीं था कि प्रत्येक अभियुक्त द्वारा विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य किया गया था। नीचे की अदालतों द्वारा देखी गई तथ्यात्मक स्थिति और धारा 149 भारतीय दंड संहिता के आवेदन को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि नीचे की अदालतों द्वारा अपीलकर्ताओं के मामले में धारा 149 भारतीय दंड संहिता को लागू करना उचित था। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत सही दोषी ठहराया गया है। ऐसा होने पर, अपीलें खारिज करने योग्य हैं, जिसका हम निर्देश देते हैं।

बी.बी.बी. अपीलें खारिज.

सुनील कुमार और अन्य बनाम राजस्थान राज्य

चंद्रकांत शुक्ल की देखरेख में शशिप्रभा द्वारा अनुवादित।